



इस्पात मंत्रालय

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने धर्मशाला में इस्पात मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की

Posted On: 10 JUN 2017 7:42PM by PIB Delhi

सदस्यों ने राष्ट्रीय इस्पात नीति **2017** और देश में उत्पादित लौह एवं इस्पात उत्पादों को सरकारी खरीद में वरीयता देने वाली नीति की सराहना की

घरेलू उपभोग बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करने और इस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर फोकस : बीरेंद्र सिंह

केंद्रीय इस्पात मंत्री, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज धर्मशाला में इस्पात मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। संसद के सदस्यों ने नई राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017 और देश में उत्पादित लौह एवं इस्पात उत्पादों को सरकारी खरीद में वरीयता देने वाली नई नीति पर चर्चा करने के साथ-साथ उसकी सराहना की।

अध्यक्ष एवं इस्पात मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस घरेलू उपभोग बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करने और देश में इस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 से सभी नीतिगत हस्तक्षेपों का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी हिस्सा शामिल नहीं है। नीति आने वाले वर्षों में उद्योग के लिए एक रोड मैप तैयार करती है और वह क्षेत्र की अनप्रयुक्त क्षमताओं को पाने में मदद करेगी। नीति, घरेलू इस्पात उद्योग के 2030-31 तक 300एमटी के स्टील बनाने की क्षमता को प्राप्त करने की महत्वकांक्षाओं को दर्शाती है। इसके चलते इस्पात क्षेत्र में लगभग 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा और 1.1 मिलियन अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

एनएसपी 2017 की मुख्य विशेषताओं में शामिल है:-

- इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना
- पर्याप्त क्षमता में वृद्धि को बढ़ावा देना,
- विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना,
- लौह अयस्क, खाना पकाने के कोयले और प्राकृतिक गैस का लागत प्रभावी उत्पादन और घरेलू उपलब्धता,
- विदेशी निवेश और कच्चे माल की परिसंपत्ति अधिग्रहण को आसान बनाना
- घरेलू स्टील की मांग में वृद्धि करना

वीके/पीएम/डी - 1716

(Release ID: 1492694) Visitor Counter : 4

